तिब्बत देश

अपने ही बारूद पर बैठा चीन का ओलंपिक सपना

पूरी दुनिया के लोग बहुत बेताबी के साथ 8 अगस्त से बीजिंग में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा आबादी वाले, सबसे बड़ी सेना वाले, सबसे ज्यादा हथियारों वाले, सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने को उतावले और बात–बात में पूरी दुनिया को सबसे बड़ा अंगूठा दिखाने वाले देश में होने जा रहे इस ओलंपिक के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार के खेल ओलंपिक के इतिहास के सबसे अनूठे खेल होंगे।

खबरों के मुताविक इस आयोजन के लिए चीन सरकार ने स्टेडियम और ओलंपिक गांव बनाने पर अरबों डालर खर्च किए हैं। प्रचार पर भी करोड़ों डालर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। चीन सरकार का इरादा चीन को दुनिया की बिरादरी में उस इज्जतदार स्थान पर बिठाना है जो चीनी शासकों की तानाशाह शासनशैली, मानवाधिकार विरोधी नीतियों और उपनिवेशवादी नजरिए के कारण चीन को आज तक हासिल नहीं हो पायी।

चीन सरकार की इस विशाल राजनीति, आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक ताकत के मुकाबिल वे लोग हैं जिनके सामने इस चीनी ओलंपिक महायज्ञ ने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। इनमें चीन के लोकतंत्रवादी संगठन हैं जो 1989 में चीनी मशीनगनों और फौजी टैंकों की चोट आज तक नहीं भूल पाए हैं। फालुन गांग, ईसाई चर्च, मुस्लिम समाज और बौद्ध धर्मावलंबी हैं जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनी दुश्मन मानकर उनके पनपने के रास्ते में हर तरह का रोड़ा अटकाती आयी है। इसके अलावा चीनी कब्जे में सांसे गिन रहे तिब्बत, सिंकियांग, इनर मंगोलिया और मंचूरिया जैसे दर्जनों छोटे–छोटे देश हैं जो साठ साल से तमाम दमन और अत्याचारों के बावजूद आजादी का सपना संजोए हुए हैं। इन सबको डर है कि ओलंपिक से चीन सरकार की इन सबके प्रति अमानवीय नीतियों को दुनिया की स्वीकृति मिल जाएगी। मानवाधिकार में विश्वास रखने वालों का कहना है कि अगर ओलंपिक से केवल चार महीने पहले तिब्बत में 209 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्या करने और हजारों को जेल में डालने के बाद भी अगर चीन सरकार ओलंपिक की वाहवाही लूट ले जाती है तो यह सभ्य दुनिया के मुंह पर तमाचा है।

लेकिन इस ओलंपिक का एक फायदा यह भी हुआ है कि चीन पर नए फोकस के कारण दुनिया का ध्यान इन समस्याओं की ओर भी जाने लगा है। संयोग से इस बिरादरी में सबसे आगे तिब्बती हैं जिनके पास दलाई लामा जैसा करिश्माई नेता है और जिन्होंने पिछले पचास साल में दुनिया भर में लाखों समर्थक भी बना लिए हैं। लेकिन यह भी सच है कि तिब्बत समर्थकों और दलाई लामा समेत इस पूरे पक्ष के पास चीन के मुकाबले नाममात्र के संसाधन भी नहीं हैं। उनकी कुल पूंजी बस केवल वह सत्य है जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा उनका अपना नैतिक साहस और समझदारी है जो उन्हें पचास–साठ साल से चीन के खिलाफ मैदान में टिकाए हुए है। यही वजह है कि आए दिन ऐसे मौके आते हैं जब चीन सरकार की बेशुमार आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक ताकत के बावजूद ऐसे संगठन बाजी मार लेते हैं। पिछले दिनों इसका एक शानदार उदाहरण ओलंपिक मशाल की विश्वयात्रा के समय देखने को मिला।

कहां एक ओर तो चीन सरकार ने मशाल की इस यात्रा को अपने लिए अश्वमेघ यज्ञ की तरह पेश करने की कोशिश की थी। बीजिंग के नेताओं ने मशाल के साथ हर देश में जबरन चीनी सुरक्षाकर्मियों का विशाल काफिला जोड़कर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था मानों यह मशाल ओलंपिक खेलों का प्रतीक न होकर चीनी विश्व विजय का अश्वमेघ घोड़ा हो। लेकिन तिब्बत समर्थक संगठनों ने देखते–देखते चीनी इरादों की हवा निकाल दी। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा देश था जहां ओलंपिक मशाल अपने पहले से तय रास्ते पर टिकी रह पायी हो। चीन के खराब मानवाधिकारों के रिकार्ड को लेकर हर जगह चीन विरोधी प्रदर्शनों ने वहां की सरकारों को मशाल का रास्ता छोटा करने पर मजबूर कर दिया। भारत में तो सरकार ने चीन सरकार को खुश करने के लिए मशाल की सुरक्षा को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था कि ओलंपिक जलूस आखिर में कई हजार वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों की हिरासत में होने वाली हास्यास्पद परेड बनकर रह गया। मशाल के साथ सबसे ज्यादा बुरा तो चीन के कब्जे में फंसे तिब्बत और सिंकियांग की राजधानियों में हुआ जहां पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने के बाद ही मशाल का जलूस निकाला जा सका। कुल मिलाकर ओलंपिक की मशाल के कारण चीन का उपनिवेशवादी चेहरा अपनी पूरी कुरूपता के साथ बेनकाब हो गया। अब आगे देखना है कि असली ओलंपिक खेलों में माहौल कैसा रहने वाला है।

जहां तक चीन की बात है, वहां की सरकार अपने परंपरागत कम्युनिस्ट अंदाज़ में सख्ती बरतते हुए यह सुनिश्चित करने पर तुली हुई है कि ओलंपिक की हर चीज़ सरकारी नेताओं द्वारा तय की गई लकीर पर चले। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो–जो कदम उठाए जा रहे हैं वे ऐसे हास्यास्पद और दादागीरी से ओतप्रोत हैं कि अगर इस सबका परिणाम उलटा न निकले तो हैरानी होनी चाहिए। चीन सरकार को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि विदेशी खिलाड़ी, विदेशी दर्शक और यहां तक कि विदेशी पत्रकार भी दलाई लामा के एजेंट हो सकते हैं और चीन विरोधी प्रदर्शन कर सकते हैं या प्रदर्शनकारियों को भड़का सकते हैं। चीनी ओलंपिक समिति ने मेहमानों पर जिस तरह की पाबंदिया लागू करने की योजना बनायी है उनमें से कई इतनी अपमानजनक हैं कि तिब्बत समर्थक संगठनों के प्रयासों के बिना ही मेहमान चीन के खिलाफ भड़क सकते हैं।

उदाहरण के लिए बीजिंग आने वाले हर खेल प्रेमी को वीज़ा और टिकट बेचने से पहले उसके बारे में यह जांच की जा रही है कि वह तिब्बत, सिंकियांग या किसी अन्य सरकार विरोधी चीनी संगठन का समर्थक तो नहीं है। कड़ाई से जांच की जाएगी कि उसके कंप्यूटर, सीडी या थंबड्राइव में कोई ऐसी फाइल, गीत या वीडियो तो नहीं है जो चीन में प्रतिबंधित है। यहां तक कि चीन पहुंचने वाले मीडिया कर्मियों और टीवी टीमों के मेकअप का सामान भी जब्त किया जा चुका है। पिछले दिनों इन हरकतों से परेशान मीडिया कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से यह शिकायत की कि टीवी प्रसारण के लिए आने वाले उनके उपकरणों को कस्टम की क्लियरेंस में इतना लंबा समय लगाया जा रहा है कि खेल शुरू होने तक वे अपने उपकरणों को फिट भी नहीं कर पाएंगे। इसके जवाब में ओलंपिक समिति पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है।

ताजा समाचारों के मुताबिक ऐसे कई स्थानों पर टीवी कंपनियों को अपने कैमरे लगाने से रोक दिया गया है जहां के लिए उन्हें पहले अनुमति दे दी गई थी। मीडिया पर एक और पाबंदी यह लगाई गई है कि किसी भी टीवी चैनेल या एजेंसी के लाइव प्रसारणों को आठ मिनट देरी से एयर करने दिया जाएगा। चीनी सैंसर अधिकारी हर टीवी सिग्नल को आठ मिनट के लूप में चलाकर पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर जाने वाली फुटेज मे किसी प्रदर्शनकारी, चीन विरोधी बैनर या तिब्बती झंडे को नहीं शामिल किया गया है। ओलंपिक के लिए आए पत्रकारों के चलने फिरने को सीमित करने और उनके विषयों को भी सेंसर करने की चीनी नीति ने मीडिया के मन में पहले से ही इतने पूर्वाग्रह और शंकाएं पैदा कर दी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी विद्रोह पर उतारू हो सकता है।

इन बातों के अलावा चीन सरकार ने तिब्बत और मशाल के सवाल पर तथा राजकीय निमंत्रण के मामले में राजनेताओं में भेदभाव करके भी अपनी साख खराब की है और कई सरकारों के साथ तनाव पैदा कर लिया है। फ्रांस का उदाहरण सबसे चिंताजनक है। आशंका यही है कि एक जगह से फूटी चिंगारी पूरे ओलंपिक को अपनी लपेट में ले सकती है।

– विजय क्रान्ति

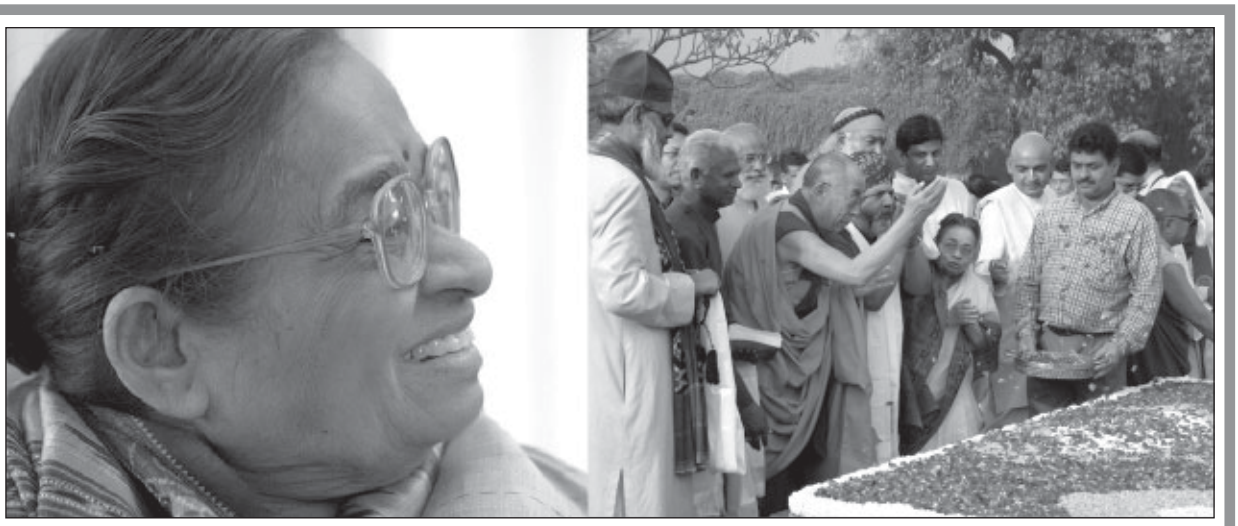

सुश्री निर्मला देशपांडे। 30 मार्च के दिन तिब्बती शहीदों की याद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में निर्मला जी धार्मिक नेताओं और दलाई लामा जी के साथ

तिब्बत की मित्र और 'दीदी' निर्मला देशपांडे पंचतत्वों में विलीन

तिब्बती समाज की स्नेहपूर्ण श्रद्धांजलि

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शोक सभा में प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे ने कहा कि तिब्बती आंदोलन में निर्मला जी के अर्थवान योगदान के लिए तिब्बती जनता उन्हें हमेशा सम्मान के साथ याद करेगी।

तिब्बत की जनता के कष्टों के बारे में चिंतित रहने वाली और उसके शांतिपूर्ण संघर्ष की प्रबल समर्थक सुश्री निर्मला देशपांडे का शरीर एक मई 2008 को पांच तत्वों में विलीन हो गया। अपने 79 साल के जीवन का 60 साल से ज्यादा हिस्सा उन्होंने सामाजिक कार्यों में बिताया।

तिब्बत समर्थकों और तिब्बती शरणार्थी समाज में 'दीदी' नाम से लोकप्रिय और गांधीवादी आदर्शों, खासकर ग्रामस्वराज को समर्पित निर्मला जी का जन्म 17 अक्तूबर, 1929 को नागपुर में हुआ था। गांधी जी के अहिंसा मार्ग और जनसेवा के आदर्शों से अंतरमन तक प्रभावित दीदी 1952 में आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गईं। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने विनोबा जी के साथ भारत के गांव–गांव तक लगभग 40 हजार किलोमीटर की पदयात्रा की। उनकी इस लगन और विनोबा जी के प्रति गहरी आस्था के कारण उन्हें उनकी 'मानसपुत्री' कहा जाता था।

विनोबा जी के स्वर्गवास के बाद भी दीदी का पूरा जीवन समाज को प्रेम और अहिंसा के रास्ते जोड़ने और सामाजिक तथा राजनीतिक विवादों को बातचीत और अहिंसा के रास्ते से हल करने पर केंद्रित रहा। पंजाब और कश्मीर में हिंसा के चरम दौर में वहां शांति यात्राओं के आयोजन में उनकी भूमिका और भारत–पाकिस्तान संबंधों को शांतिपूर्ण बनाने की उनकी पहल ने पिछले कम से कद दो दशक के दौरान उन्हें शांतिदूत की छवि प्रदान की है। उनकी इस गांधीवादी छवि के लिए उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी चर्चित रहा।

तिब्बत के सवाल को हल करने के लिए परमपावन दलाई लामा के 'मध्य मार्ग' को दीदी का पूरा समर्थन था और भारत की गांधीवादी बिरादरी के बीच 'तिब्बत का गांधी' के रूप में मशहूर तिब्बती प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे के साथ उन्हें अक्सर सार्वजनिक मंचों पर देखा जाता था।

सुश्री निर्मला देशपांडे के निधन का समाचार भारत के तिब्बती शरणार्थी समाज में भारी दुख के साथ सुना गया। 2 मई को उनके अंतिम संस्कार के समय पूरे तिब्बती समाज और तिब्बत सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दलाई लामा के प्रतिनिधि और मंत्री श्री तेम्पा सेरिंग, तिब्बती संसद की उपाध्यक्षा सुश्री दोलमा ग्यारी, कई संसद सदस्य और तिब्बती युवा कांग्रेस के नेता तथा दिल्ली में तिब्बती समर्थक संगठनों और तिब्बती समाज के लगभग एक सौ प्रतिनिधि और भिक्षु उपस्थित थे।

16 मई के दिन नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शोक सभा में धर्मशाला से तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए प्रधानमंत्री प्रो. सामदोंग रिंपोछे ने कहा कि तिब्बती आंदोलन में निर्मला जी के अर्थवान योगदान के लिए तिब्बती जनता उन्हें हमेशा सम्मान के साथ याद करेगी। अहिंसा के रास्ते विवादों को हल करने में उनकी आस्था और विश्वास के बारे में उन्होंने कहा कि ये आदर्श हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी भरोसेमंद मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। उन्हें सही श्रद्धांजलि यही है कि हम भी अपने कार्यों में इन आदर्शों का पालन करें।

फोटो : विजय क्रान्ति

दिल्ली में राजघाट पर दलाई लामा : शांति का रास्ता

हू जिंताओ को दलाई लामा का सहारा लेना चाहिए

प्रो. रोबर्ट थुर्मन ने चीन सरकार को तिब्बत का शांतिपूर्ण हल खोजने की सलाह दी

(तिब्बत में चीन विरोधी जनांदोलन के उभरने पर पश्चिम के विद्वान प्रो. राबर्ट थुर्मान ने वाशिंगटन पोस्ट के 26 मार्च के अंक के लिए एक टिप्पणी लिखी जिसमें उन्होंने चीन सरकार, खासकर राष्ट्रपति हू जिंताओ को सलाह दी है कि वह दलाई लामा के साथ टकराव के बजाए उनकी सलाह का गंभीरता पूर्वक पालन करें।)

नयी सदी की शुरुआत में हम मानवता के महत्त्वपूर्ण दोराहे पर खड़े हैं। यह सदी या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का गवाह बन सकती है या पर्यावरण संरक्षण एवं शांतिपूर्ण वैश्विक समुदाय की दृष्टि से इतिहास में दर्ज होने वाली महान सदी। परमपावन दलाई लामा मौजूदा समय के सभी वैश्विक नेताओं में से सर्वाधिक धार्मिक, बुद्धिजीवी और मानवतावादी नेता समझे जाते हैं, जिन्होंने शांति और खुशी का मार्ग दिखाया है। पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता का यही रहस्य है। उनका व्यक्तित्व और उपदेश केवल तिब्बतियों ही नहीं, चीनियों और हम सभी तथा हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

यदि दुनिया में विश्वास और धार्मिक पहलुओं को ध्यान में रखकर कभी किसी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की बात चलेगी तो दलाई लामा द्वारा 50 वर्ष से चलाये जा रहे इस अभियान और तिब्बतियों के अचानक बगावत करने को जरूर याद किया जाएगा। तिब्बती नागरिक अध्यात्मिक गुरू और राजनीतिक नेता की उपस्थिति में अपने अध्यात्मिक जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए आजाद बनने की आस लगाए हुए हैं। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक 'चीन' की संहारक कार्रवाइयों के बावजूद दलाई लामा का सत्य और अहिंसा एवं बातचीत के रास्ते पर अडिग रहना और तिब्बतियों की अपनी धरती मां को आजाद कराने की जिजीविषा के चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं। दुनिया के सबसे 'गये–गुजरे' मामले में भी अनोखी सफलता मिल सकती है।

तिब्बती नागरिक जान जोखिम में डालकर अपनी संस्कृति, पर्यावरण और जीवन जीने के तरीके को संरक्षित करने के लिए संघर्षरत हैं। तिब्बती नागरिक यह सब कुछ अहिंसा के रास्ते हासिल करना चाहते हैं जो सुखद है, लेकिन समय की मार, दशकों की खटास और मौजूदा स्थिति की भयावहता को देखते हुए हाल के दिनों में कुछ तिब्बती अपने संघर्ष के मूल सिद्धांत 'अहिंसा' को भुला बैठे हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। तिब्बतवासियों ने चीन की क्रूरता के समक्ष घुटने नहीं टेके, बल्कि सीना तानकर उनकी गोलियां का सामना किया। उन्हें पता था कि ये गोलियां उनकी जान ले लेंगी लेकिन वे डटे रहे।

हालांकि, दलाई लामा ने कभी किसी को इस रास्ते पर चलने की सीख नहीं दी। उन्होंने कहा है कि तिब्बती यदि हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो वे इस्तीफा दे देंगे। दलाई लामा के अनुयायियों ने उनमें असाधारण विश्वास प्रदर्शित किया है। अब चीनी नेताओं के पास बहुत बड़ा अवसर है। पिछले साठ साल से वे तिब्बत को चीन बनाने और तिब्बतियों को चीनवासियों के रूप में तब्दील करने में जुटे हैं। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। दलाई लामा चीन के इस प्रयास को सांस्कृतिक जनसंहार की संज्ञा देते हैं। चीन अपनी योजना में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। बल्कि अपनी इस असफलता के लिए वे दलाईलामा के कथित गुट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

परम पावन दलाई लामा को जीवित गांधी, अहिंसा के पुजारी, बौद्ध का अवतार माना जाता है। तमाम झंझावातों के बावजूद दलाई लामा ने दोस्ती का हाथ बढाया है और वे चाहते हैं कि तिब्बत समस्या का सर्वमान्य हल हो जाए, जिससे चीन के साथ–साथ तिब्बत के लोग भी संतुष्ट हों। यह समय है कि चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ को चाहिए कि वह दलाई लामा का सहारा लें।

(रॉबर्ट थुरमन कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में धर्म विभाग के इंडो– तिबेतन बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोफेसर हैं।)

चीन की संहारक कार्रवाइयों के बावजूद दलाई लामा का सत्य, अहिंसा और बातचीत के रास्ते पर अडिग रहना और तिब्बतियों की धरती मां को आजाद कराने की जिजीविषा के चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं।

फोटो : विजय क्रान्ति

दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान शूटिंग करते तेनजिंग सोनाम : अनुभवी फिल्मकार

शांति मार्च की ऐतिहासिक आवश्यकता

धर्मशाला से भारत–तिब्बत सीमा तक की 110 दिन की शांति पदयात्रा के बारे में तिब्बती फिल्मकार का अनुभव

– तेनजिंग सोनम

मेरा मानना है कि इस पदयात्रा का महत्त्व अब केवल इस बात से नहीं आंका जा सकता कि तिब्बत वापसी का इसका लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। वापसी पदयात्रा निर्वासित तिब्बतियों से संबंधित राजनीति के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेतक है।

'वतन को वापसी' पदयात्रा कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के सीमावर्ती सुदूर पर्वतीय शहर धारचुला के प्रवेश द्वार पर समाप्त हो गयी। इस यात्रा के अंतिम बचे 50 पदयात्रियों ने उन सैकड़ों पुलिसकर्मियों के समक्ष शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे दी जिन्होंने पदयात्रा के तमाम रास्तों पर नाकेबंदी कर रखी थी। धर्मशाला से शुरू हुई और धारचुला में समाप्त हुई इस पदयात्रा को लगातार कैमरे में कैद करने के लिए हम पदयात्रियों के साथ लगातार बने हुए थे।

सेराघाट और बांसपतन में पुलिस नाकेबंदी के दौरान मैंने पदयात्रियों के साथ खुले आसमान के नीचे 14 दिन बिताये। मेरा मानना है कि इस पदयात्रा का महत्त्व अब केवल इस बात से नहीं आंका जा सकता कि तिब्बत वापसी का इसका लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। वापसी पदयात्रा निर्वासित तिब्बतियों से संबंधित राजनीति के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेतक है। अपने ही नेताओं के विरोध और तीखी आलोचना के बावजूद इस तरह की पहल को आम तिब्बती नागरिकों की ओर से की गयी पहली वास्तविक लोकतांत्रिक पहल के रूप में याद रखा जा सकता है।

इस कार्य के लिए ''टिबेटन पीपुल्स अपराइजिंग मूवमेंट'' के बैनर तले पांच गैर सरकारी संगठन इकट्ठे हुए थे जिनके राजनीतिक उद्देश्य अलग–अलग हैं। यह अपने आप में प्रशंसनीय प्रयास है। उन पांचों संगठनों के लिए एक बैनर के नीचे इस तरह का प्रयास करना आसान नहीं था, खासकर तब जब इन संगठनों में ऐसे भी तत्व शामिल थे जो इस तरह के सहयोगात्मक प्रयास के विरुद्ध थे और पदयात्रा की योजना पर पानी फेरने में जुटे हुए थे।

पदयात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब व्यक्तिगत संगठन अपने–अपने मतभेदों को भुलाकर व्यापक और समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं तो वे न केवल प्रभावशाली तरीके से संबंधित कार्य को अंजाम दे सकते हैं, बल्कि समाज के व्यापक हिस्से की भागीदारी और सहयोग भी हासिल कर सकते हैं। बांसपतन में नाकेबंदी के दौरान मुझे पदयात्रियों के निकट रहने और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

सबसे अच्छी चीज जिसने मुझे प्रभावित किया वह थी कि पदयात्रियों ने सम्पूर्ण तिब्बती समाज का प्रतिनिधित्व किया। पदयात्रियों में सबसे युवा व्यक्ति 17 साल का था जबकि सबसे वृद्ध व्यक्ति की आयु 70 वर्ष के पार थी। पदयात्रियों में तिब्बत से आए नये लोग भी शामिल थे तो सम्पूर्ण जीवन निर्वासन में बिताने वाले तिब्बती भी। बौद्धभिक्षु भी थे और भिक्षुणियां भी। आम आदमी भी थे। पूरी आजादी के कट्टर समर्थक भी थे तो वैसे लोग भी थे जो वास्तविक स्वायत्तता के लिए आजादी और मध्यम मार्ग दोनों के पक्ष में हैं।

पदयात्रियों में जबर्दस्त एकजुटता थी और इसे उन्होंने अप्रत्याशित तरीके से प्रदर्शित किया। उदाहरण के तौर पर पहली बार जब पुलिस सख्ती से पेश आई और पदयात्रियों को डराने धमकाने लगी तो पदयात्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया गीत गाकर और नृत्य कर व्यक्त की। वैसे युवा भिक्षु, जो हाल ही में खम के तावु क्षेत्र से भागकर भारत आए थे उन्होंने भी अपनी जवानी के गीत गाए और नृत्य से पदयात्रियों को रोमांचित किया। जैसे ही पदयात्रियों ने तोएपा गोर्शे नृत्य (गोल–गोल घूमकर नृत्य करना) शुरू किया और तिब्बत के दो परम्परागत क्षेत्रीय समूह आम्दो और खम्पा अपने साथी मध्य तिब्बती बंधु–बांधवों के साथ घुले–मिले तो शिविर में पुलिस के कारण व्याप्त तनाव कम हो गया।

बांसपतन में गर्मी काफी अधिक थी। लंबी और उमस भरी दोपहरी में अनेक टेंटों में बहस छिड़ी हुई थी। एक बहस को मैंने अपने कैमरे में कैद भी किया। एक समूह के भिक्षु इतने जोशीले और निर्मम प्रतीत हो रहे थे कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति देखता तो ऐसा

लगता कि वे लोग आपस में भिड़ने वाले हैं। एक दूसरे को धक्का देकर वे लोग गर्मागर्म बहस में शामिल थे और उनके बहस का विषय था– तिब्बती संघर्ष में आजादी और मध्यम मार्ग की अच्छाई और बुराइयों का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों तरह के सिद्धांतों के प्रस्तावक अपने–अपने तर्क से अपना रुख सही साबित करने में जुटे थे जबकि इस बहस को बाहर से देख रहे तमाशबीन बीच–बीच में अपनी टिप्पणियों के साथ इसमें शामिल हो रहे थे।

अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बहस विभिन्न शिविरों में अलग–अलग आवाजों में लगातार सुनने को मिली। हर बहस में उतना ही उत्साह और जोश मौजूद था। हमारे राजनीतिक आंदोलन की दिशा क्या हो, इस बारे में इस तरह के उत्साहपूर्ण एवं खुली बहस हमारे निर्वासित समुदाय में विरले ही सुनने को मिलती है। मैं इस बात से काफी उत्साहित था, क्योंकि चीजें बदल रही हैं।

धर्मशाला में पदयात्रा शुरू होने से पहले मैंने अनेक पदयात्रियों का साक्षात्कार किया था। मैंने उनसे एक सवाल यह भी किया था कि यदि दलाई लामा उनलोगों को पदयात्रा रोकने को कह दें तो वे लोग क्या करेंगे? जिनके मैंने साक्षात्कार किये उनमें युवा और वृद्ध भिक्षु–भिक्षुणियां और आम आदमी भी शामिल थे। इनमें शायद ही कोई कट्टर कार्यकर्ता हों। इनमें अधिकांश साधारण तिब्बती थे और अपने धर्मगुरू दलाई लामा के प्रति निष्ठावान थे। इसके बावजूद उनमें से एक ने बेहिचक जवाब दिया कि वे पदयात्रा जारी रखेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कह रहा है? उन्होंने वादा किया है कि वे उसे निभाने के लिए कृतसंकल्प हैं। उनका मानना है कि वे लोग एक अहिंसक अभियान में जुटे हैं, जो तिब्बती समस्या के लिए लाभकारी है।

उनके संकल्प की उस वक्त जांच हुई जब पहले नवगठित 'सोलिडैरिटी कमेटी' ने और बाद में दलाई लामा ने खुद आयोजकों को पदयात्रा खत्म करने को कहा। लेकिन दबाव के बावजूद पदयात्रा जारी रही। इस घटना के बाद एक बार फिर मैंने अनेक पदयात्रियों से पूछा कि आखिर दलाई लामा की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाने का फैसला क्या सोचकर किया? उनलोगों में से कुछ ने जो जवाब दिया उसकी राजनीतिक परिपक्वता से मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि दलाई लामा संपूर्ण मानवता के लिए अंतहीन करुणा के अपने सिद्धांत से बंधे हैं और इसीलिए वह ऐसे किसी भी कदम का समर्थन

'वतन की ओर पदयात्रा' के दौरान पदयात्री दिल्ली में : अहिंसा की ताकत

करने में अक्षम हैं, जिससे चीनी या भारतीय अधिकारियों के साथ टकराव बढ़ने की आशंका हो। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार उनलोगों पर भी कुछ करने की जिम्मेदारी है और जबतक उनलोगों का अंतःकरण शुद्ध है और उनके कदम अहिंसक हैं, तबतक वे लोग अपने धार्मिक नेता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं हैं।

इस प्रकार इसमें 10 मार्च 1959 के ल्हासा जनांदोलन की भावना ही प्रतिबिम्बित होती है, जब हजारों तिब्बतियों ने दलाई लामा की सुरक्षा के मद्देनजर बार–बार अपील करने के बावजूद नोर्बुलिंका पैलेस छोड़ने से मना कर दिया था। धारचुला में जिस दिन पदयात्रियों को बस में ठूंसा जा रहा था और उत्तराखंड से बाहर भेजा जा रहा था, मुझे बहुत ही दुख हुआ था, लेकिन मैं तब भी आशावादी बना रहा। हालांकि मैंने जो कुछ देखा वह किसी खास मायने में एक अभियान का अंत भले ही कहा जाए, लेकिन यह व्यक्तिगत जिम्मेदारियों वाली राजनीतिक सक्रियता की नयी शुरुआत थी।

हममें से किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कब या कैसे तिब्बत की स्थिति सुधरेगी, लेकिन हम निर्वासित तिब्बती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का इस्तेमाल कर या उसे अमल में लाकर लोकतांत्रिक आधार को और मजबूत जरूर कर सकते हैं। लोकतांत्रिक रूप से मजबूत निर्वासित तिब्बत भविष्य में तिब्बती लोगों की उम्मीदों और प्रोत्साहन का एक मात्र स्रोत हो सकता है।

(तेनजिंग सोनम और उनकी पत्नी रितु सरीन मशहूर फिल्म 'ड्रीमिंग ल्हासा' के निर्माता निर्देशक है। वे आजकल नयी दिल्ली में रह रहे हैं। वे दोनों व्हाईट क्रेन फिल्म्स के निर्देशक हैं।)

इसमें 10 मार्च 1959 के ल्हासा जनांदोलन की भावना ही प्रतिबिम्बित होती है, जब हजारों तिब्बतियों ने दलाई लामा की सुरक्षा के मद्देनजर बार–बार अपील करने के बावजूद नोर्बुलिंका पैलेस छोड़ने से मना कर दिया था।

फोटो : विजय क्रान्ति

बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबुर्ग गेट पर दलाई लामा को सुनने आई जर्मन भीड़ और मंच पर दलाई लामा : समर्थन का सैलाब

इक्कीसवीं सदी खूनखराबे की नहीं बल्कि बातचीत और शांति की सदी होगी

जर्मन जनता के दिल में बसते हैं दलाई लामा

*('तिब्बत–देश' के संपादक **विजय क्रान्ति** तिब्बत पर अपनी फोटो प्रदर्शनी 'टू फेसिस ऑफ टिबेट' के सिलसिले में मई में जर्मनी में थे जब दलाई लामा अपनी यात्रा पर वहां आए। इस प्रदर्शनी का आयोजन जर्मनी के सबसे प्रमुख तिब्बत समर्थक संगठन टिबेट इनिशिएटिव डायट्शलैंड, टीआईडी ने किया था जो दलाई लामा जी की जर्मन यात्रा का भी मेजबान था। टीआईडी के निमंत्रण पर श्री विजय क्रान्ति ने दलाई लामा जी की यात्रा के आधिकारिक फोटोग्राफर के तौर पर उनके साथ जर्मन शहरों की यात्रा की। प्रस्तुत रिपोर्ट उसी अनुभव पर आधारित है।)*

जर्मनी जैसा अनुशासित देश, बर्लिन जैसा व्यस्त शहर और उस पर मंगलवार का दिन –– कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ब्रांडेनबुर्ग गेट पर किसी का भाषण सुनने के लिए 25 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं।

किसी पश्चिमी देश में किसी प्रदर्शन में दो चार सौ लोगों का जुटना या किसी राजनेता को सुनने के लिए दो हजार लोगों का इकट्ठा होना अगले दिन के अखबारों के लिए बड़ी सुर्खियों का मसाला होता है। ऐसे आयोजन के लिए महीनों तैयारी चलती है और सभा के लिए छुट्टी का दिन चुना जाता है ताकि इच्छुक लोगों को आने में मुश्किल न हो।

ऐसे में जर्मनी जैसा अनुशासित देश, बर्लिन जैसा व्यस्त शहर और उस पर मंगलवार का दिन –– कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि शहर के ऐतिहासिक ब्रांडेनबुर्ग गेट पर किसी का भाषण सुनने के लिए 25 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ऊंचाई पर बने मंच से मैं अपने कैमरे का वाइड एंगल उसकी आखिरी सीमा तक ले जाता हूं। लेकिन मंच के बायीं ओर दूर तक खड़ी भीड़, सामने दूर वहां तक सिरों और झंडों का सैलाब जहां तक नजर जा सकती है और मंच के दाएं ओर नजर की सीमा तक फैले लोगों को अपनी स्क्रीन पर पकड़ने के लिए मुझे तीन दिखाओं में तीन बार शूट करना पड़ता है। जर्मनी में दलाई लामा की लोकप्रियता का अजब आलम है।

यह मंगलवारए 20 मई का दिन है। हैरान होने वालों में अकेला मैं ही नहीं, इस सभा के आयोजक वोल्फगांग ग्राडेर भी हैं जो टिबेट इनिशिएटिव डायट्शलैंड, टीआईडी के अध्यक्ष हैं। पिछले पांच दिन से वह और उनकी टीम के अधिकाश सदस्य दलाई लामा की पांच दिवसीय जर्मन यात्रा के दौरान एक शहर से दूसरे शहर उनके साथ चल रहे थे। आज सुबह तक वह इस बात से चिंतित थे कि वर्किंग–डे की इस सभा में लोग आएंगे भी या नहीं। उनकी टीम ने इस जनसभा का फैसला केवल दस दिन पहले ही किया गया था और तैयारी के नाम पर एक–दो अखबारों में विज्ञापन और कुछ पर्चे–स्टिकर ही बांटे जा सके थे। कई जर्मन पत्रकारों और फोटोग्राफरों का कहना था कि लंबे समय से उन्होंने ब्रांडेनबुर्ग गेट पर ऐसी विशाल और उत्साही भीड़ नहीं देखी थी।

इससे पहले बोखुम, बामबेर्ग और न्यूरेमबर्ग के ठसाठस स्टेडियमों में भी मैं ऐसा नज़ारा देख चुका था। लेकिन उन सभाओं के आयोजन के लिए वोल्फगांग और उनके साथियों ने छह महीने तैयारी की थी। हर जगह एक जैसा उत्साह, एक जैसी दीवानगी। दलाई लामा की एक झलक पाने और हाथ मिलाने को आतुर शहर के मेयर से लेकर सड़क किनारे बच्चे और तिब्बती झंडे के साथ घंटों इंतजार करती जर्मन माताएं। और उसके बाद, दलाई लामा को सामने देख टपाटप आंसू टपटपाते, मुस्कराते हुए लोग.....।

यह सब देख मुझे उन खबरों का मतलब समझ आने लगा जो कुछ महीने पहले पढ़ी थीं –– एक खबर : *10 मार्च के दिन 1200 से ज्यादा जर्मन शहरों की म्युनिसपैलिटियों ने अपने सरकारी दफ्तरों पर तिब्बती झंडा फहराया*; दूसरी खबर : *जर्मन लोगों में*

♦ दलाई लामा

दलाई लामा जर्मन पोप से भी ज्यादा लोकप्रिय.....।

15 मई को इस यात्रा के पहले दिन फ्रेंकफर्ट हवाई अड्डे पर हैस्से प्रांत के मुख्यमंत्री श्री रोलांड कॉख़ ने उनका स्वागत किया। पहला कार्यक्रम बोखम में था जहां प्रांत के मुख्यमंत्री श्री युरगेन रुटजेर्स ने उनका स्वागत किया। बोखम में दलाई लामा ने स्थानीय इनडोर स्टेडियम में तीन हजार से ज्यादा लोगों के सामने 'मानवाधिकार और वैश्वीकरण' विषय पर व्याख्यान दिया। अपने इस व्याख्यान में उन्होंने कहा कि नई शताब्दि में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस शताब्दि को शांति और बातचीत के रास्ते विवाद सुलझाने वाली सदी बनाना होगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने पूरी दुनिया की सरकारों का आहवान किया कि वे सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने का फैसला करें।

बोखम में स्थानीय सिटी मेयर ने दलाई लामा के लिए एक विशेष नागरिक सम्मान समारोह में उन्हें शहर के प्रवेश द्वार की चाबी भेंट की। यूरोप में किसी नगर द्वारा किसी मेहमान को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। चाबी भेंट करने का मतलब हमारे नगर में आप जब चाहें अधिकार पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा ही न्यूरेमबर्ग के मेयर ने भी किया।

बोखम में दलाई लामा एक स्थानीय चर्च के किंडरगार्टन के बच्चों के भी मेहमान बने। वहां बच्चों के साथ उन्होंने लगभग एक घंटे तक बातचीत की। इस बातचीत का एक मुख्य आकर्षण वह हिस्सा था जिसमें दलाई लामा ने छोटे बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनके गीतों में शामिल हुए।

बोखम के बाद वह श्लेश्विग होलस्टाइन में एक सार्वजनिक समारोह में गए। वहां से वह न्यूरेमबर्ग गए। वह वहां की विख्यात 'मेंशनरेश्टे श्ट्रासे' (मानव अधिकार स्ट्रीट) में गए जहां इज़राइल के एक विख्यात कलाकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणपत्र की सभी 24 धाराओं को मानवाधिकारों से वंचित समाजों को समर्पित खंभों पर उनकी भाषा में उकेरा है। यहां दलाई लामा ने तिब्बती भाषा वाले खंभे के सामने एक ज्योतिदीप जलाया, उस खंभे को तिब्बती शुभकामनाओं वाला एक स्कार्फ बांधा और वहां उपस्थित चीनी विद्यार्थियों के आग्रह पर चीनी भूकंप में मारे गए और पीड़ित लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की।

बाद में टिबेट इनिशिएटिव डायट्श्लैंड द्वारा आयोजित एक विशाल सभा में उन्होंने भाषण दिया। वहां के सबसे बड़े इनडोर स्टेडियम की दर्शक दीर्घा के अलावा पूरे एरेना में लगाई गई सभी सीटें भरी हुई थीं। साढ़े सात हजार से ज्यादा दर्शक। एक हिंदुस्तानी होने के नाते पहली बार देखा कि 30 यूरो (1800 रु) का टिकट खरीद कर सुने गए भाषण और मुफ्त वाली भीड़ की आस्था में कितना अंतर होता है। आयोजकों का कहना था कि हाल और प्रचार का खर्चे निकालने के लिए टिकट बहुत जरूरी हैं।

19 मई के दिन बर्लिन पहुंचने पर जर्मन सरकार के विकास मंत्री श्री वीज़ोरेक ज़ेउल ने उनके साथ सरकारी स्तर पर भेंट की जिसपर चीन सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज करायी। लेकिन इसके बावजूद दलाई लामा को जर्मनी की विदेश मामलों से संबंधित संसदीय समिति को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।

20 मई को ब्रांडेनबुर्ग गेट पर अपने भाषण में दलाई लामा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, ''बीसवीं सदी खूनखराबे वाली सदी थी। मेरी इच्छा है कि 21वीं सदी को हम लोग बातचीत वाली सदी बनाएं।''

हर जगह एक जैसा उत्साह, एक जैसी दीवानगी। दलाई लामा की एक झलक पाने और हाथ मिलाने को आतुर शहर के मेयर से लेकर सड़क किनारे बच्चे और तिब्बती झंडे के साथ घंटों इंतजार करती जर्मन माताएं। और उसके बाद, दलाई लामा को सामने देख टपाटप आंसू टपटपाते, मुस्कराते लोग.....

कैमरे की

1. बीजिंग ओलंपिक के जवाब में तिब्बती शरणार्थी समाज ने 25 मई के दिन
2. 'वतन की ओर' शांति पदयात्रा को उत्तराखंड में पुलिस ने रोक लिया। ए
3. तिब्बत की 'फ्रीडम ओलंपिक टार्च' पूरी दुनिया की यात्रा के दौरान 3 मई
4. नई दिल्ली में तिब्बती ओलंपिक मशाल के स्वागत समारोह में समर्थन दे
5. दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में आए दलाई लामा ने
6. 19 मई के दिन चीनी नेताओं पर तिब्बत में नरसंहार के मुकदमे के लिए
7. न्यूयार्क में तिब्बती युवा कांग्रेस की रैली में इंडियन आयडल प्रशांत तामां
8. जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में दलाई लामा ने मानवाधिकार स्ट्रीट में शांतिदीप ज
9. जर्मनी के बामबेर्ग शहर में दलाई लामा को सुनने के लिए वहां का इनडो
10. जार्डन में 18 जून के दिन नोबेल विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग

♦ आंखों देखी

ी आंख से

न धर्मशाला में 'तिब्बत ओलंपिक–2008' का आयोजन किया।

क पहाड़ी मार्ग पर धरने पर बैठे पदयात्रियों में से एक पदयात्री।

के दिन ऑस्लो पहुंची।

ने आए कई नेताओं में से श्री जार्ज फर्नांडीज़ और श्री कीर्ति आज़ाद।

जामा मस्जिद की प्रार्थना सभा में भाग लिया।

स्पेन की सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने जाते हुए दो तिब्बती भिक्षु।

ा और नेपाली पॉप आयडल राजू लामा तिब्बती झंडे के साथ।

लाया और तिब्बत को समर्पित खंभे को स्कार्फ बांधा।

ोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था।

लेने आए दलाई लामा अरब लीग के अध्यक्ष अमीर मूसा के साथ।

(फोटो 4,8 और 9 : विजय क्रान्ति)

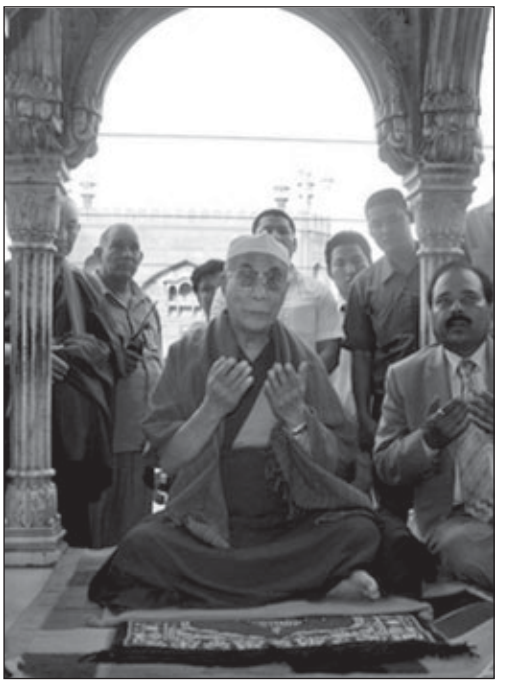

तिब्बती प्रदर्शनकारियों की पैरवी : दो चीनी वकीलों के लाइसेंस रद्द

ह्यूमन राइट्स वाच ने वकीलों और कानून फर्मों के खिलाफ चीनी अभियान की निंदा की

न्यूयॉर्क : मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच के मुताबिक तिब्बती प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता से वंचित रखा जा रहा है। संगठन का कहना है कि इन गिरफ्तार तिब्बतियों की पैरवी की इच्छा जाहिर करने वाले दो प्रमुख वकीलों तेंग बिआवो और जियांग तियानयोंग के लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी गई है। गत मार्च और अप्रैल में पूरे तिब्बत में हुए चीन विरोधी प्रदर्शनों में हजारों तिब्बतियों को गिरफ्तार किया गया था।

चीन सरकार ने कानूनी फर्मों को धमकाते हुए कहा है कि वे राजनैतिक रूप से संवेदनशील मामलों को अपने हाथ में न लें। इसका मतलब उन्हें तिब्बती राजनीतिक कैदियों की ओर से अदालत में पेश होन से रोकना है। सरकार के इस कदम से वकीलों से संबंधित कानून में पिछले दिनों किए गए संशोधन का कोई अर्थ नहीं रह गया है।

चीन सरकार ने कानूनी फर्मों को धमकाते हुए कहा है कि वे राजनैतिक रूप से संवेदनशील मामलों को अपने हाथ में न लें। इसका मतलब उन्हें तिब्बती राजनीतिक कैदियों की ओर से अदालत में पेश होन से रोकना है। वॉच का कहना है कि सरकार के इस कदम से वकीलों से संबंधित कानून में पिछले दिनों किए गए संशोधन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। 1 जून 2008 से लागू होने वाले इस संशोधन में वकीलों की पेशेगत सुरक्षा के नए प्रावधान किए गए हैं।

चीन में वकीलों को हर साल अपने लाइसेंस का नवीकरण कराना होता है। बीजिंग न्यायिक ब्यूरो ने इस बार तेंग बिआवो और जियांग तियानयोंग के प्रोफेशनल लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया है। सिविल और मानवाधिकारों के मामलों में इन दोनों वकीलों का शानदार रिकार्ड रहा है। ब्यूरो ने एक दर्जन से अधिक कानून फर्मों के सालाना रजिस्ट्रेशन में भी कई हफ्तों का विलंब किया। इनमें से कई फर्मों ने अपने यहां ऐसे वकीलों को नियुक्त किया है जो सरकार के मुताबिक 'संवेदनशील केस' लड़ने में शामिल थे। कुछ वकीलों ने छिपे तौर पर ब्यूरो की कार्रवाई की निंदा की है। उनका कहना है कि यह 'बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल' है जिसका मकसद कानून फर्मों को ऐसे मामले हाथ में लेने से रोकना है जो सरकार को उलझन में डाल सकते हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर सोफी रिचर्डसन ने कहा, ''बीजिंग सरकार ने उक्त दो वकीलों के लाइसेंसों को निलंबित कर दिया है और कई वकीलों को उनके लाइसेंसों का नवीकरण न करने की धमकी है। इस तरह वह कानून के पेशे को धमकाने की कोशिश कर रही है। बीजिंग का मकसद वकीलों को मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करने से रोकना है।''

अप्रैल के शुरू में सरकार ने घोषणा की थी कि ल्हासा में मार्च के विरोध प्रदर्शनों में शामिल सैकड़ों तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घोषणा के बाद 18 मशहूर वकीलों वाले एक नागरिक अधिकार ग्रुप ने एक खुला पत्र जारी कर बंदियों को कानूनी सहायता देने की पेशकश थी। पत्र में कहा गया था, ''पेशेवर वकील के रूप में हम उम्मीद करते हैं कि संबद्ध अधिकारी तिब्बती बंदियों के साथ संविधान, कानून और आपराधिक प्रतिवादी प्रक्रिया के अनुसार पेश आएंगे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि बंदियों से जबर्दस्ती इकबालिया बयान नहीं लिया जाएगा और न्यायिक स्वतंत्रता तथा कानून का पालन किया जाएगा।''

खुला पत्र जारी होने के तुरंत बाद न्याय मंत्रालय ने उस पर दस्तखत करने वाले वकीलों और उनकी फर्मों को धमकी दी कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि वकील और बार एसोसिएशन न्याय मंत्रालय के मातहत हैं। बीजिंग के न्यायिक अधिकारियों ने कानून फर्मों से कहा है कि उक्त अपील पर दस्तखत करने वाले वकीलों से वे अपने को अलग कर लें या उन्हें बरखास्त कर दें।

न्यायिक अधिकारियों ने कई फर्मों को लिखित में सूचित किया कि, ''आपकी फर्म के वकील कुछ संवेदनशील मामलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए आपकी फर्म की सालाना जांच और उसके रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से लंबित किया जाता है।''

राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारियों ने भी कई वकीलों को चेतावनी दी कि वे तिब्बती प्रतिवादियों के संबंधियों की तरफ से दी जाने वाली फीस स्वीकार न करें। बीजिंग बार एसोसिएशन ने इन वकीलों पर ''दलाई लामा मंडली को समर्थन देने'' का आरोप लगाया है।

एक दूसरे खुले पत्र में, जो रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने से एक हफ्ता पहले 24 मई को प्रकाशित हुआ था, पहले पत्र पर दस्तखत करने वाले वकीलों ने कहा कि उनकी पेशकश का उद्देश्य तिब्बतियों को बचाना था। इसलिए, उनकी पेशकश को तिब्बती अलगाववाद के विचारों का समर्थन नहीं माना जा सकता। चीन के कानून के तहत, तिब्बती अलगाववाद राज्य की सुरक्षा के खिलाफ अपराध माना जाता है।

ओलंपिक के बाद भी मानवाधिकार सुधारों के लिए चीन पर दबाव जारी रहना चाहिए

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तिब्बत में अत्याचारों पर चीन की निंदा की

लंदन, 28 मई एमनेस्टी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि बीजिंग ओलंपिक के बाद भी चीन पर मानवाधिकार सुधारों के लिए दुनिया का दबाव जारी रहना चाहिए।

रिपोर्ट जारी करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल की प्रमुख आइरीन खान ने कहा कि बंदियों को यातना देना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, मृत्युदंड देना, अखबारों पर सेंसरशिप थोपना, सभाओं पर प्रतिबंध लगाना और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना अभी भी चीन में आम बात है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत में धार्मिक आजादी पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है और तिब्बतियों के आध्यात्मिक तथा राजनैतिक नेता दलाई लामा के समर्थकों को 'कठोरता से दंडित' किया जाता है।

खान ने रिपोर्ट के प्रकाशन के मौके पर एक इंटरव्यू में कहा, ''मेरे ख्याल से ओलंपिक खेलों के बाद चीन पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। यह एक ऐसी चुनौती होगी जो खबरों के एजेंडेसे अक्सर फिसल सकती है।'' एमनेस्टी की सेक्रट्री जनरल ने कहा कि हमने 2007 में चीनी सिविल सोसाइटी में 'कुछ सुधार' देखा है। वहां मृत्यु दंड के मामले में खुली सुनवाई और अपील की दिशा में कुछ पहल हुई है। इसके अलावा, विदेशी मीडिया को भी रिपोर्टिंग की इजाजत दी जा रही है।

सुश्री खान ने कहा कि चीन ने दार्फुर में अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना की तैनाती का समर्थन किया है। इसके अलावा, उसने पिछले साल म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों पर सैन्य अत्याचार के बाद वहां बीच–बचाव में भी मदद की। लिहाजा उसके इस रवैए से 'उम्मीद की किरण' जागी है। लेकिन बीजिंग को अभी भी काफी कुछ करना है। उसे यह महसूस करना चाहिए कि जिम्बाब्वे, उत्तरी कोरिया, म्यांमार और दार्फुर में व्यावसायिक स्तर पर ही सही, स्थिरता को बढ़ावा देना उसके हित में हो सकता है।

सुश्री खान ने आगे कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि चीन अंततः मानवाधिकारों का मूल्य समझना शुरू कर देगा।'' एमनेस्टी के अनुसार मानवाधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा के 60 साल बाद 2007 में भी दुनिया में मानवाधिकारों की स्थिति ठीक नहीं है। पाकिस्तान में अशांति, केन्या में चुनाव बाद की हिंसा और म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों का दमन यही दर्शाता है कि मानवाधिकारों के मुद्दों से निपटने में पश्चिम 'अक्षम' है। इसके अलावा, उभरती विश्व शक्तियां भी मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर या तो दुविधा में हैं या फिर वे उन्हें सुलझाना नहीं चाहतीं।

खान ने रिपोर्ट की भूमिका में कहा, ''आज अन्याय, और असमानता हमारी दुनिया की विशेषताएं बन चुकी हैं। इसलिए सरकारों को अब कथनी और करनी के बीच की चौड़ी होती खाई को पाटने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा कि 2008 के सबसे बड़े मुद्दे दार्फुर, जिम्बाब्वे, गाजा, इराक और म्यांमार हैं। उन्होंने वहां की सरकारों से अपील की वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई संयुक्त राष्ट्र संधि के मूल सिद्धांतों का पालन करें।

उन्होंने कहा, ''ताकतवर देशों को अपने अच्छे कार्यों से दुनिया के सामने मिसाल पेश करनी चाहिए।'' अमेरिका, जहां इस साल नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, को चाहिए कि वह संदिग्ध इस्लामिक आतंकवादियों के लिए बनाए गए गुआंटोनामो बेस कैंप को बंद कर दे, बंदियों पर मुकदमा चलाए या उन्हें रिहा कर दे और 'वाटरबोर्डिंग' सरीखी यातना पूरी तरह से खत्म कर दे।

रिपोर्ट में अमेरिका की अगुआई में की जा रही 'गुप्त और गैरकानूनी गिरफ्तारियों' में यूरोपीय संघ के शामिल होने की आलोचना की गई है। असंतोष और आलोचना के प्रति रूस की बढ़ती असहिष्णुता की भी आलोचना की गई है।

एमनेस्टी ने कहा कि पिछले 60 साल में कई सकारात्मक घटनाएं हुई हैं जिनमें मृत्युदंड का व्यापक उन्मूलन, मानवाधिकार कानून का बनना और युद्ध संबंधी अपराधों के लिए मुकदमे चलाना शामिल हैं। म्यांमार में हाल में हुए विरोध प्रदर्शन यह दर्शाते हैं कि 'जनशक्ति' को दबाया नहीं जा सकता।

सुश्री खान ने कहा ''सन् 2008 महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से हम एक विशेष रास्ते पर चलते रहे हैं। हम पश्चिम और बाकी दुनिया को अलग–अलग नजरिए से देखते रहे हैं। यह बहुत नुकसानदेह रहा है। यह अच्छाा संकेत है कि अब नई अवधारणाएं आकार ले रही हैं, नए सेतु बनाए जा रहे हैं और नए मौकों का सृजन किया जा रहा है। जब आप इन चीजों को जनता के दबाव से जोड़ देंगे तो आपको एक खूबसूरत आशावादी भविष्य बनता नजर आएगा।''

रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत में धार्मिक आजादी पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है तिब्बतियों के आध्यात्मिक तथा राजनैतिक नेता दलाई लामा के समर्थकों को 'कठोरता से दंडित' किया जाता है। ओलंपिक खेलों के बाद चीन पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। यह एक ऐसी चुनौती होगी जो खबरों के एजेंडेसे अक्सर फिसल सकती है।''

वार्ता के बाद तिब्बती प्रतिनिधि लोडी ग्यारी और केलसांग ग्याल्तसेनः वार्ता मे विश्वास

चीन–तिब्बत वार्ताओं पर फ्रांस पर नजर रखे हुए हैं – सरकोज़ी

फ्रांस के राष्ट्रपति और आस्ट्रिया के चांसलर ने चीन को बीजिंग ओलंपिक के बारे में सचेत किया

फ्रांस इस बात से वाकिफ है कि यूरोप में तिब्बत और ओलंपिक संवेदनशील मुद्दे हैं। इसलिए फ्रांस ने दोनों तरफ अपनी आंखें खुली रखी हैं। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बारे में अंतिम फैसला करने से पहले मैं घटनाओं पर नजर रखूंगा।

विएना, 30 मई फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने कहा है कि बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निर्णय लेने से पहले हम चीन और दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली वार्ता की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आस्ट्रिया के चांसलर अल्फ्रेड गुसेनबोएर से विएना में भेंट करने के बाद कहा, ''वार्ता में प्रगति है जो सकारात्मक है।'' उन्होंने आगे कहा, ''फ्रांस इस बात से वाकिफ है कि यूरोप में तिब्बत और ओलंपिक संवेदनशील मुद्दे हैं। इसलिए फ्रांस ने दोनों तरफ अपनी आंखें खुली रखी हैं। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बारे में अंतिम फैसला करने से पहले मैं घटनाओं पर नजर रखूंगा।''

खबरों के मुताबिक फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा कि पिछले महीने पेरिस में ओलंपिक मशाल जुलूस के दौरान हुए प्रदर्शनों के कारण चीनी पर्यटन विभाग फ्रांस का बहिष्कार कर रहा है। चीनी पर्यटकों की फ्रांस यात्राओं को नियोजित तरीके से रद्द किया जा रहा है जिसका फ्रांसीसी पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। श्री गुसेनबोएर ने कहा कि वे सामान्य तौर पर अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के बहिष्कार से असहमत हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि तिब्बत से हिंसा की खबरें आती हैं तो उद्घाटन समारोह में जाना 'असंभव' होगा। श्री गुसेनबोएर की बीजिंग यात्रा की योजना नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रिया के नेता ओलंपिक के उद्घाटन समारोहों में शामिल होने को अधिक महत्व नहीं देते। उन्होंने कहा, ''मैं नहीं सोचता कि हम इस नीति को बदलेंगे।''

स्टोन : चीन का भूकंप तिब्बत मे चीन के पापों का नतीजा है

हॉलिवुड की विख्यात अभिनेत्री शेरॉन स्टोन ने कान फिल्म महोत्सव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तिब्बत में चीनी सरकार की कार्रवाइयों की आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन में आया भूकंप चीन सरकार द्वारा तिब्बती जनता पर किए गए पापों का नतीजा है। दुर्भाग्य से इसका नुकसान चीनी जनता को भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा, ''मेरी समझ में नहीं आता कि हम बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के बारे में क्या नजरिया अपनाएं। दलाई लामा, जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, के प्रति चीन का रवैया शोभाजनक नहीं है।''

पचास वर्षीय शेरॉन ने कहा ''चीन में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर मैंने सोचा कि यह सब कर्मों का फल है। अगर आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो आप पर विपत्ति ही आएगी।''

शेरॉन की इस टिप्पणी पर चीन सरकार और चीनी मीडिया में भयंकर प्रतिक्रिया हुई है। इसके तुरंत बाद चीनी मीडिया में शेरॉन के खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार शुरू हो गया। चीन में शेरॉन स्टोन की फिमें दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एक यूट्यूब वीडियो में दिखाई गई स्टोन की इस टिप्पणी ने ऑनलाइन कम्युनिटी और चीनी फिल्म उद्योग के सदस्यों को बहुत नाराज कर दिया है। फैडरेशन ऑफ हांगकांग फिल्म मेकर्स के अध्यक्ष और यूएमई सिनेप्लेक्स चेन के संस्थापक नग सी.युएन ने बीजिंग टाइम्स से कहा कि स्टोन की टिप्पणियां 'अनुचित' हैं। उन्होंने कहा कि उनका सिनेमा चेन, जिसकी हांगकांग, बीजिंग और शंघाई में कई सिनेप्लेक्स हैं, स्टोन अभिनीत कोई फिल्म नहीं दिखाएगा।

सौंदर्य प्रसाधनों की दिग्गज कंपनी क्रिश्चियन डायओर की जनसंपर्क कंपनी ने भी स्टोन के खिलाफ कार्रवाई की है। उसने बीजिंग के डिपार्टमेंट स्टोरों से उन सभी पोस्टरों को हटा दिया है जिनमें स्टोन को कंपनी के उत्पादों के साथ दिखाया गया है। यह प्रतिबंध चीनी सिनेमा प्रेमियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। प्रतिबंध से प्रभावित होने वाली स्टोन की पहली फिल्म 'द इयर ऑफ गेटिंग टु नो अस' के बारे

में इंटरनेट फिल्म साइट आइएमडीबी के एक यूजर ने अपनी कड़वी टिप्पणी देते हुए इसे अपने जीवन में देखी गई पांच सबसे घटिया फिल्मों में से एक बताया है।

भारत की धार्मिक सहिष्णुता विश्व के लिए आदर्श है : दलाई लामा

नई दिल्ली तिब्बत के निर्वासित शासक और तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की सराहना करते हुए कहा है कि उसकी 'धार्मिक सहिश्णुता' बाकी दुनिया के लिए आदर्श बन सकती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में कहा, ''भारत की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा लम्बे समय से चली आ रही है। भारत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख सरीखे दुनिया के प्रमुख धर्मों का जन्मदाता है और उसने जरथुष्ट जैसे धर्मों के अनुयायियों को अपने यहां शरण दी है। बाकी दुनिया इससे सबक ले सकती है।''

उन्होंने पाकिस्तान और इराक, जहां शिया–सुन्नी झगड़े में हजारों जानें जा चुकी हैं, का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में सभी धर्मों और पंथों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। उन्होंने दुनियाभर में फैल रहे आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा, ''कुछ लोगों की कार्रवाई से पूरा समुदाय बदनाम होता है। यह गलत है। हम लोगों को मानव मूल्यों की कद्र करनी चाहिए और मानवता के बारे में समग्रता से सोचना चाहिए। यह सार्वभौमिक जिम्मेदारी है। सभी प्रमुख धर्म इस ग्रह पर वास्तविक शांति ला सकते हैं। इसलिए मेरा पूरी दुनिया से अनुरोध है कि वे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दें।''

दलाई लामा ने कहा, ''हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। भावात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर हम एक हैं। इसलिए हमें अपने हितों के लिए छह खरब लोगों के कल्याण का ध्यान रखना होगा।'' उन्होंने यहां आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कुछ शरारती लोगों के सोच और कार्यों के कारण सभी मुसलमानों को आतंकवादी कहना बिलकुल गलत है। ''कुछ शरारती लोगों के सोच और उनके कार्यों से पूरा धर्म बदनाम होता है। इन घटनाओं के कारण यह छाप पड़ती है कि सभी मुसलमान लड़ाकू हैं। यह गलत है। मैं बौद्ध हूं लेकिन इस्लाम का बचाव कर रहा हूं।''

केंद्रीय विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल राजनैतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसे चुनावी मुद्दा बनाने से आतंकवादियों को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद की तुलना एचआइवी से करते हुए श्री सिब्बल ने कहा, ''बीमारी कोई किसी भी देश की सीमा को नहीं पहचानती। हमें आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक सहयोग और समझ की जरूरत है। जो देश अपने संकीर्ण राजनैतिक फायदे के लिए आतंकवादियों को हथियार और पैसा दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की गतिविधियां बंद कर देनी चाहिएं।''

चीनी जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ी

हाल के आंदोलनों के सिलसिले में हुई गिरफ्तारियों की वजह से ल्हासा और इसके आसपास की जेलों में तिल रखने की जगह नहीं है। इन जेलों में क्षमता से कहीं अधिक कैदी हैं। ल्हासा की निकटवर्ती काउंटियों से गिरफ्तार किये गये प्रदर्शनकारियों को स्थानीय काउंटी जेलों में रखा जा रहा है, क्योंकि ल्हासा की बड़ी जेल भर चुकी है।

ल्हासा नगर निगम के तहत ताकत्से में 14 और 15 मार्च को प्रदर्शन हुए थे, जिनमें कुछ युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब उनके अभिभावकों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है।

तिब्बती नागरिकों का विरोध प्रदर्शन

न्यूजलाइन के सौजन्य से : नासिक में तिब्बती समुदाय की खासी आबादी है। देशभर में फैले अपने हम वतनों के साथ एकता जताने के लिए तिब्बतन फाउंडेशन फॉर सॉलिडैरिटी ने जिला कलकेक्टर के कार्यालय के सामने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।

इस मौके पर तिब्बती फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया और मोमबत्तियां जलाकर चीन सरकार के हाथों मारे गए 200 से ज्यादा तिब्बती प्रदर्शनकारियों के लिए प्रार्थना की। इस विरोध प्रदर्शन में तिब्बती फाउंडेशन को स्थानीय तिब्बत समर्थकों ने भी सहयोग दिया।

तिब्बती प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि तिब्बत में चीन सरकार द्वारा की गई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। उसकी यह भी मांग थी कि सं. रा. संघ तिब्बत को अपनी निगरानी में ले ताकि तिब्बती जनता के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। तिब्बती नेताओं ने कहा कि तिब्बती जनता हिंसा के बजाए अहिंसा और बातचीत के रास्ते अपनी राष्ट्रीय समस्या का हल चाहती है।

भारत की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा लम्बे समय से चली आ रही है। भारत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख सरीखे दुनिया के प्रमुख धर्मों का जन्मदाता है और उसने जरथुष्ट जैसे धर्मों के अनुयायियों को अपने यहां शरण दी है। बाकी दुनिया इससे सबक ले सकती है। कुछ शरारती लोगों की सोच और उनके कार्यों से पूरा धर्म बदनाम होता है। इन घटनाओं के कारण यह छाप पड़ती है कि सभी मुसलमान लड़ाकू हैं। यह गलत है। मैं बौद्ध हूं लेकिन इस्लाम का बचाव कर रहा हूं।

धर्मशाला के टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज में आयोजित 'तिब्बत ओलंपिक–2008' के कुछ दृश्य : अधिकारों के लिए संघर्ष

'तिब्बत ओलंपिक–2008' ने समां बांधा

बीजिंग ओलंपिक के जवाब में तिब्बती शरणाथी समाज ने तिब्बती ओलंपिक का आयोजन किया

एस्तोनिया के सांसद श्री सिल्वर माइकार ने ओलंपिक मशाल से ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया। यह मशाल पिछले पांच महीने के दौरान दिल्ली से सिडनी, ताइपे, तोक्यो, हवाई, सान फ्रांसिस्को, न्यूयार्क सिटी, रिओ डे जेनेरे, लंदन, केप टाउन और तेल अवीव से होती हुई धर्मशाला पहुंची थी।

मैक्लोडगंज, धर्मशाला 25 मई के दिन तिब्बती शरणार्थी समाज ने बीजिंग ओलंपिक के प्रति विरोध दर्ज करने के लिए धर्मशाला में अपने ही स्तर पर 'टिबेटन ओलंपिक–2008' का आयोजन किया जो कई मायनों में नाटकीय भी रहा और मर्मस्पर्शी भी। यह आयोजन बच्चों के गांव 'टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज' (टीसीवी) के विशाल मैदान में किया गया।

पिछली रात में तेज बारिश के कारण आयोजकों को चूने की लाइनों को नए सिरे से लगाना पड़ा जिसके कारण खेल समारोह आधा घंटा देरी से शुरू हुआ। समारोह की शुरुआत ओलंपिक परेड से हुई जिसमें सबसे आगे तिब्बती और ओलंपिक ध्वज चल रहे थे। इसके पीछे टीसीवी के मार्चिंग बैंड, फिर पिछले वर्षों की चार मिस–तिब्बत सुंदरियों और उनके पीछे तिब्बती पुरुष और महिला खिलाड़ी टीमों ने हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया।

समारोह में विशेष तौर में भाग लेने के लिए एस्तोनिया के एक संगीत बैंड के साथ आए वहां के सांसद श्री सिल्वर माइकार ने ओलंपिक मशाल से ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया। यह मशाल पिछले पांच महीने के दौरान दिल्ली से सिडनी, ताइपे, तोक्यो, हवाई, सान फ्रांसिस्को, न्यूयार्क सिटी, रिओ डे जेनेरे, लंदन, केप टाउन और तेल अवीव से होती हुई धर्मशाला पहुंची थी। तिब्बती खिलाड़ियों की ओर से सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक दावा दाक्पा ने मशाल सौंपी और खिलाड़ियों की ओर से ओलंपिक शपथ ली। इस अवसर पर आर–59 बैंड ने विशेष रूप से तैयार किया गया तिब्बती ओलंपिक गीत भी गया गया। समारोह के संचालक लोबसांग वांग्याल ने अपने भाषण में इस आयोजन के उद्देश्य और रास्ते में आयी समस्याओं के बारे में बताया।

भारत के चर्चित तीरंदाजी कोच श्री शिहान हुसैनी ने सभी खिलाड़ियों की वार्म–अप ड्रिल कराई। इसके बाद ट्रैक एंड फील्ड ईवेंट्स में 80 मीटर बाधादौड़, 80 मीटर फर्राटा, लांग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो और 400 मीटर डैश की प्रतियोगिताएं हुईं। दौड़ों में खिलाड़ियों की गति इतनी तेज थी कि कुछ धावक फोटो लेने के लिए ट्रैक पर आ गए कुछ उत्साही अंतर्राष्ट्रीय कैमरामैनों से टकरा गए। दावा दाक्पा इस बार अपने हाई जंप का तिब्बती रिकार्ड तोड़ना चाहते थे लेकिन इससे पहले की दौड़ों से वे इतना थक चुके थे कि वह केवल 5फुट 4इंच की ऊंचाई की पार कर सके। तिब्बती ओलंपिक टीम के अलावा इसमें विदेशी संवाददाताओं की संयुक्त टीम ने भी हिस्सा लिया। दोर्जी सेरिंग और सेरिंग ल्हामों को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी घोषित किया गया।

खेलों के अंत में श्री सिलवर माइकार, सुश्री आशा रेड्डी और श्री कालसांग धोदुप ने विजेताओं को पदक दिए। जीतने वालों को गोल्ड, सिलवर और कांस्य पदक के साथ क्रमशः 1 लाख, 50 हजार और 25 हजार रु के ईनाम भी घोषित किए गए। शाम को टीपा आडिटोरियम में एस्तोनिया के बैंउ 'फ्लावर्स आफ रोमांस', बूम–बूम, धर्मा बम्स और आर–59 बैंडों ने संगीत पेश किया। लेकिन बाद में पैसे की कमी को देखते हुए दान के लिए सार्वजनिक अपील जारी की ताकि विजेताओं को नकद पुरस्कारों का भुगतान किया जा सके।

तिब्बत मुक्ति–साधना का तूफान पूरे तिब्बत में फैला, दुनिया की आंखें खुलीं

10 मार्च, से तिब्बत में उठी जनक्रान्ति और चीनी दमन का तिथिवार विवरण–3

25 मार्च, 2008

10 मार्च को तिब्बत में शुरू हुए आंदोलन के प्रारंभ से ही सभी मठों के बाहर और भीतर सेना और पुलिस की उपस्थिति बढ़ी। तिब्बत में हाल के प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले मठों – सेरा, द्रेपुंग और गंदेन में चीनी सेना और पीएपी के जवानों ने पानी, बिजली, खाद्यान्न और स्वास्थ्य सुविधाओं को रोक दिया।

ल्हासा के रामोचे मठ में 14 मार्च से ही चीनी सैनिकों की सख्त उपस्थिति हो गयी थी। सैनिकों ने मठ के प्रवेश और निकास मार्गों पर सख्त घेरा डाल रखा था। कड़े प्रतिबंधों की वजह से खाद्यान्न और पानी की आपूर्त्ति सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। 23 मार्च को थोकमेयी लोबसांग भिक्षु की मौत हो गयी। अगले दिन 25 मार्च को चीनी अधिकारियों ने लोबसांग का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। लेकिन अधिकारियों की ओर से मौत के कारणों के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया गया। बीच–बीच में चीनी सैनिकों द्वारा मठ परिसरों के भीतर आंसू गैस के गोले भी फेंके जाते रहे हैं।

खाने–पीने के सामान की कमी, इधर–उधर निकलने पर प्रतिबंध और मठों में आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटनाएं हर जगह हो रही हैं।

सिचुआन प्रांत की **देरोंग** और **बाथांग काउंटियों** में चीन सरकार ने कुछ मठों को 20 हजार युआन और प्रत्येक परिवार को 300 किलोग्राम चावल दिए हैं। यह बहुत ही हास्यास्पद है कि एक ओर तो चीन सरकार तिब्बतियों के दमन की हरसंभव कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर चावल बांटकर तिब्बतियों का दिल भी जीतना चाहती है।

सिचुआन प्रांत की **द्राकगो काउंटी** के तहत **चोकरी गांव** में 24 मार्च को न्नांगखोंग भिक्षुणी मठ की 200 भिक्षुणिओं ने तेहोर टाउनशिप के सरकारी मुख्यालय तक मार्च किया। मुख्यालय पर जाकर भिक्षुणिओं ने 'दलाई लामा जिन्दाबाद' और 'तिब्बत एक आजाद देश है' के नारे लगाए। उनके इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग भी शामिल हो गए। इनके साथ **चोकरी मठ** के 200 भिक्षु और **खासुम** मठ की 150 भिक्षुणिआं भी शामिल हो गयीं। अपराह्न चार बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन पांच बजे तक चला।

प्रदर्शन के दौरान चीनी सेना की गोलीबारी में चोकरी मठ का एक 21 वर्षीय भिक्षु मारा गया। सैनिकों ने उस भिक्षु का शव अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश की लेकिन तिब्बती नागरिकों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सैनिकों से शव छीन लिया और बाद में उसे गुप्त स्थान पर छिपा दिया। एक और प्रदर्शनकारी सेवांग धोंदुप भी सैनिकों की गोली का शिकार हो गया। उसकी किडनी में गोली लगी है और बचने की संभावना बहुत ही क्षीण है।

25 मार्च को सेना के हेलीकॉप्टर क्षेत्र में निगरानी के लिए लगातार उड़ान भरते रहे। शाम को कर्फ्यू भी लगाया जाता रहा।

चिंघाई प्रांत की **थांग काउंटी** में **होल्खा** टाऊनशिप के सैकड़ों तिब्बती नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन के मुख्यालय पर करीब साढ़े दस बजे प्रदर्शन शुरू किया और यह अपराह्न एक बजे तक चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बैनर लिया हुआ था जिसपर लिखा था– ''शांति, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और शहीदों के प्रति समर्थन''। दूसरे बैनर पर चीनी भाषा में लिखा था, ''तिब्बत में दमन और उत्पीड़न पर रोक लगाओ।''

सिचुआन प्रांत की **लिथांग** काउंटी में सैनिकों का जमघट लगा दिया गया। सैन्यकर्मियों के लिए 100 से अधिक शिविर बनाये गये। इसी काउंटी में एक सरकारी कार्यालय में आग लगा दी गयी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस घटना में अपने हाथ होने से इनकार किया है। तिब्बती नागरिकों का मानना है कि यह काम खुद चीनी अधिकारियों का है जो तिब्बतियों की छवि धूमिल करना चाहते हैं।

26 मार्च, 2008

ल्हासा में कड़े प्रतिबंधों का सिलसिला जारी रहा। चीनी सेना ने **त्सुगलांखांग मंदिर** और **बारखोर** में अपना शिकंजा और कस दिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ल्हासा इलाके में दुकानें बंद रहीं। अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहे अभिभावकों को घर लौटने पर मजबूर किया गया।

चीनी अधिकारियों ने **सिचुआन** प्रांत में **कारजे** स्थित **चोकरी मठ** के भिक्षुओं को मठ छोड़ने के निर्देश दिये हैं। नांगगोंग भिक्षुणी मठ की भिक्षुणिओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। हालांकि गिरफ्तारियों के भय से अनेक भिक्षुणिआं भाग निकलने में सफल रही हैं।

द्राकगो काउंटी स्थित मठों और मकानों में

सिचुआन प्रांत की लिथांग काउंटी में सैनिकों का जमघट लगा दिया गया। सैन्यकर्मियों के लिए 100 से अधिक शिविर बनाये गये। इसी काउंटी में एक सरकारी कार्यालय में आग लगा दी गयी। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस घटना में अपने हाथ होने से इनकार किया है। तिब्बती नागरिकों का मानना है कि यह काम खुद चीनी अधिकारियों का है जो तिब्बतियों की छवि धूमिल करना चाहते हैं।

चीनी सैनिकों का तलाशी अभियान जारी है। अनेक भिक्षुओं और स्थानीय नागरिकों के ठौर–ठिकाने ज्ञात नहीं हैं।

चीनी सुरक्षाकर्मियों की गोली से मारे गये **चोकरी मठ** के भिक्षु कूंगा का शव जहां स्थानीय नागरिकों ने छुपाकर रख दिया था, वहां से चीनी सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने उसे बरामद कर लिया और नजदीक में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

मृतक की आत्मा की शांति के लिए जब **चोकरी मठ** के भिक्षुओं ने प्रार्थना सभा आयोजित की तो उसमें स्थानीय लोग भी जुड़ गये। संख्या बल अधिक होने के बाद इस प्रार्थना सभा ने विरोध–प्रदर्शन का रूप ले लिया और वे लोग स्थानीय काउंटी मुख्यालय की ओर रवाना हुए, लेकिन उन्हें बड़ी संख्या में तैनात चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ने से रोक दिया।

आंदोलनकारियों को तितर–बितर करने के लिए सेना की ओर से हवा में गोलियां चलाई गईं। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा। चीनी सैनिकों की बंदूकें जब प्रदर्शनकारियों के सामने तन गयीं तो भिक्षुओं और आम नागरिकों ने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। बाद में वे लोग अपनी शर्तों पर प्रदर्शन स्थल से हटने को राजी हो गये। प्रदर्शन के दौरान कितने लोग मारे गये या कितने घायल हुए, इसका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं हो सका है।

25 मार्च की शाम के बाद से **चोकरी मठ** को चीनी सैनिकों ने घेर लिया और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। **चिंघाई प्रांत** की **गेपा सुमदो** काउंटी स्थित **सेरलेक मठ** के भिक्षुओं ने भी चीन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

इसी प्रांत की **द्राकगो काउंटी** में 24 और 25 मार्च को सफलतापूर्वक किये गये विरोध प्रदर्शनों के बाद चीनी अधिकारियों ने कम से कम 20 मोटरसाइकिलें जब्त की। इसका सीधा मतलब प्रदर्शनकारियों के इधर–उधर जाने पर प्रतिबंध लगाना और गिरफ्तारी से बचने के उनके प्रयासों पर विराम लगाना है।

ल्हासा में प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए तैनात सैनिकों की 26 मार्च के अपराह्न तीन बजे से वापसी शुरू हो गयी। हालांकि ल्हासा में स्थायी रूप से तैनात पीएसबी और कानून–व्यवस्था लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के जवान अड्डा जमाए रहे। उधर एक जनसभा के आयोजन को देखते हुए चीनी पुलिसकर्मियों ने **चोकरी मठ** के पूर्व प्रमुख नामग्याल सेरिंग और मठ के सहयोग से संचालित स्कूल के प्रधानाचार्य सोनम गुरमे को उठा लिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने की घोषणा की।

सिचुआन प्रांत की **दार्त्सेदो काउंटी** में तिब्बतियों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसका विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

25 और 26 मार्च

सिचुआन प्रांत की **नाग्चू काउंटी** स्थित **मीन्याक** शहर में चीन के करेंसी नोटों पर लोगों ने तरह–तरह के नारे लिखकर अपने गुस्से का इजहार किया। आंदोलनकारी करेंसी नोटों पर 'तिब्बत एक स्वतंत्र देश है' लिखकर उसे इधर उधर बिखेरने लगे। (चीन में 10–20 पैसे के नोट भी प्रचलित हैं)।

27 मार्च

तिब्बत में प्रेस की आजादी पर कुठाराघात करने के लिए भी चीन को तीखी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। अंत में चीन सरकार ने अपनी मर्जी के विदेशी पत्रकारों का चयन कर उन्हें तिब्बत की यात्रा करायी। विदेशी मीडिया की यात्रा के दौरान चीन की ओर से यह दिखाने का असफल प्रयास किया गया कि ल्हासा में स्थिति सामान्य हो चुकी है। निश्चित तौर पर यह यात्रा चीन सरकार प्रायोजित थी और इस दौरान बहुत सावधानी बरती गयी।

विदेशी पत्रकारों का दल जब **सुगलाखांग मंदिर** पहुंचा तो वहां चीन सरकार द्वारा चुने गए तीन भिक्षुओं ने पत्रकारों से बातचीत की और अन्य भिक्षुओं को यह निर्देश दिया गया था कि वे मठ की अन्य गतिविधियों में लिप्त प्रतीत हों। मीडिया दल जब मंदिर की यात्रा कर रहा था उस वक्त वहां सभी भिक्षुओं को दार्शनिक शास्त्रार्थ में व्यस्त दिखाया गया। लेकिन मंदिर की मात्र पंद्रह मिनट की इस यात्रा के दौरान कुछ भिक्षु विदेशी मीडिया के सामने अचानक जा पहुंचे और उन्होंने विदेशी पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया कि तिब्बत में धार्मिक आजादी नहीं है। कुछ भिक्षुओं ने रोते हुए कहा कि तिब्बत में आंदोलन के लिए परमपावन दलाई लामा को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इन भिक्षुओं की इस साहसिक कार्रवाई ने चीन सरकार के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बाद में इन भिक्षुओं को यह बयान देते हुए दुनिया भर के टीवी चैनलों पर दिखाया गया। उक्त भिक्षुओं की हालत क्या हुई इसकी कोई खबर नहीं है।

मंदिर की मात्र पंद्रह मिनट की इस यात्रा के दौरान कुछ भिक्षु विदेशी मीडिया के सामने अचानक जा पहुंचे और उन्होंने विदेशी पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया कि तिब्बत में धार्मिक आजादी नहीं है। कुछ भिक्षुओं ने रोते हुए कहा कि तिब्बत में आंदोलन के लिए परमपावन दलाई लामा को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इन भिक्षुओं की इस साहसिक कार्रवाई ने चीन सरकार के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया।

26 मार्च को **त्सेगोर थांग काउंटी** में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गयी एक युवती और रिबुनग्याल नामक एक युवक की रिहाई की मांग के समर्थन में मुख्यालय के समीप इकट्ठा होकर तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया। दोनों में से किसी को भी रिहा किया गया या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है।

अगले अंक में जारी .....